Hindustan Times, Delhi
Thursday, 14th November 2019; Page: 22
Width: 5.59 cms; Height: 9.30 cms; a4; ID: 24.2019-11-14.185

NHRC organises one-day national seminar

The National Human Rights Commission organised a one-day national seminar on 'Elimination of Bonded Labour System' at India International Centre under the Chairmanship of Justice PC Pant, Former Judge of Supreme Court and member, NHRC.

Santosh Kumar Gangwar, Minister of Labour and Employment, Government of India was chief guest of the seminar while Justice HL Dattu, Chairperson, NHRC inaugurated it. The inaugural session began with the welcome speech of Jaideep Govind, Secretary General, NHRC.

Dainik Jagran, New Delhi
Thursday, 14th November 2019; Page: 15
Width: 16.43 cms; Height: 21.67 cms; a4; ID: 21.2019-11-14.147

मानवाधिकारों पर बनी लघु फिल्मों को मिला सम्मान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को लघु फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी है। आयोग ने देश भर से आई 88 लघु फिल्मों की प्रविष्टियों में से तीन को चुना है, जिन्हें 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

आयोग ने पहले स्थान पर लघु फिल्म 'कुंभिल शिवा' को चुना है, जिसके निर्देशक महाराष्ट्र के रहने वाले विशाल कुंभार हैं। उन्हें एक लाख रुपये दिए जाएंगे। फिल्म में बच्चों के यौन शोषण की कहानी को दर्शाया गया है। आयोग ने किन्नरों के जीवन से जुड़ी कहानी को दूसरे स्थान पर रखा है और 75 हजार रुपये का पुरस्कार देने का फैसला किया है। इस फिल्म का नाम 'ट्रांसजेंडर' है और इसके निर्देशक तमिलनाडु निवासी अर्नेस्ट रोसारियो हैं। तीसरे स्थान पर 'गल्प' नामक लघु फिल्म है, जिसके निर्देशक केरल निवासी विजेंद्र श्याम हैं। फिल्म

बाल यौन शोषण पर आधारित 'कुंभिल शिवा' को मिला पहला पुरस्कार, विजेताओं को प्रोत्साहन के साथ नकद राशि भी मिलेगी

शहरीकरण से होने वाले प्राकृतिक संपदा के नुकसान की कहानी को बयां करती है। फिल्म को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आयोग ने चार अन्य फिल्मों को भी चुना है, जिन्हें 'स्पेशल मेंशन' के खिताब से नवाजा जाएगा। इनमें के. जयचंद्र हाशमी की 'टू लेट', शुभ्रा दीक्षित की 'डाइंग विश', येंग चेन थापा की 'नीमा' व आर. रवि प्रसाथ की 'डू स्पीट हीयर' शामिल हैं। इन अवार्ड के पीछे आयोग का मकसद देश के अलग-अलग कोने से आने वाली मानवाधिकार से जुड़ी फिल्मों को प्रोत्साहित करना है। यह 5वां वर्ष है, जब आयोग की तरफ से इस तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं।